हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

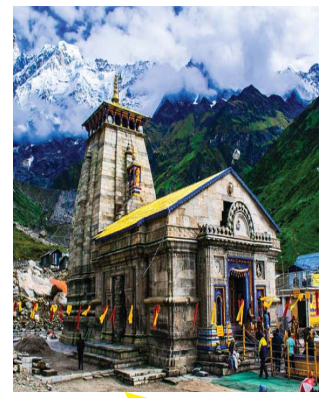

वर्ष:4 अंक:283 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने टनकपुर को दी 36.30 करोड़ की सौगात, 15 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

पथ प्रवाह, टनकपुर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को क्रीड़ा स्थल छीनीगोठ, टनकपुर में आयोजित ÷मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव÷ कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन सहित कुल 15 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुल 36.30 करोड़ की लागत वाली योजनाओं को जनता को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इन योजनाओं से टनकपुर क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को नई दिशा मिलेगी और यह सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण उत्थान का आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रीप परियोजना के तहत प्रेरणा स्वयं सहायता समूह (स्हात) की महिलाओं को 5 ई-रिक्शा प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला समूह की प्रतिनिधियों को 'खुशियों की चाबी' सौंपते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा, ÷यह ई-रिक्शा केवल वाहन नहीं है, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और गरिमा की नई पहचान है। इससे महिलाएं बेहतर आय अर्जित करेंगी और पारंपरिक पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को 'सहायता प्राप्तकर्ता' नहीं, बल्कि 'सशक्त उद्यमी' के रूप में स्थापित करना है। इस प्रकार के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सकें।

09 योजनाओं का लोकार्पण - 9.38 करोड़ की लागत से

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 9 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें प्रमुख हैं

❍मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन का लोकार्पण (45.00 लाख) - प्रशासनिक भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ जनता और प्रशासन के बीच संवाद और समन्वय को सुदृढ़ किया जाएगा।

❍राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागपुर एवं जूनियर हाई स्कूल फागपुर को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया गया (76.40 लाख)।

❍राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर का पुनर्निर्माण (74.50 लाख)।

❍डेविड पेंटर स्कूल, गुदमी में दो कक्षा-कक्ष का निर्माण (16.00 लाख)।

❍भैंसियाखाल एवं बिचाई पंपिंग पेयजल योजनाओं का लोकार्पण (136.77 लाख + 182.61 लाख)।

❍कोतवाली टनकपुर में सिटी कंट्रोल रूम की स्थापना और यातायात व्यवस्था सुधार (239.05 लाख)।

❍पर्यटक आवास गृह का उच्चीकरण (68.00 लाख)।

❍एनएचपीसी बनबसा द्वारा पावर स्टेशन मुख्य गेट से पाटनी तिराहा तक सड़क मरम्मत (100.00 लाख)।

❍06 योजनाओं का शिलान्यास - 26.93 करोड़ की लागत से

❍मुख्यमंत्री ने 6 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें शामिल हैं÷

❍राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में परीक्षा हॉल का निर्माण (826.99 लाख)।

❍लादीगाड़ श्री पूर्णागिरी एवं ठुलीगाड़/बाबलीगाड़ पंपिंग पेयजल योजना (811.70 लाख + 712.87 लाख)।

❍ग्राम खिरद्वारी में बुक्सा एवं राजी जनजाति के लिए बहुउद्देशीय भवन का निर्माण (60.00 लाख)।

❍प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बनबसा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना (50.00 लाख)।

❍ग्राम चुका, टनकपुर में शेड निर्माण (231.00 लाख) - मां पूर्णागिरि धाम आने वाले यात्रियों के लिए।

अदाणी समूह केदारनाथ धाम में बनायेगा देश का पहला 3S ट्राइ-केबल रोपवे

36 मिनट में पूरी होगी 9 किमी की कठिन चढ़ाई

पथ प्रवाह, नवीन चौहान

केदारनाथ धाम की कठिन और खड़ी चढ़ाई अब जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए आसान होने जा रही है। अदाणी समूह उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक देश का पहला 3S ट्राइ-केबल रोपवे सिस्टम बना रहा है। लगभग 12.9 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से तीर्थयात्रियों की यात्रा न केवल सुविधाजनक बल्कि सुरक्षित और समय की दृष्टि से भी अत्यंत लाभदायक होगी।

गौतम अदाणी बोले – यह भक्ति और आधुनिकता के बीच सेतु है

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए इस परियोजना को पुण्य कार्य बताया। उन्होंने लिखा कि केदारनाथ धाम की कठिन चढ़ाई अब आसान होगी। अदाणी समूह श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए यह रोपवे बना रहा है। इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय बाबा केदारनाथ! उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, बल्कि भक्ति और आधुनिक बुनियादी ढांचे के बीच एक सेतु है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

लंबाईः 12.9 किलोमीटर (सोनप्रयाग से केदारनाथ तक)

प्रकारः देश का पहला 3S ट्राइ-केबल रोपवे सिस्टम

निर्माण अवधि÷ 6 वर्ष

संचालन अवधि: 29 वर्ष (अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा)

यात्रा समयः वर्तमान 8-9 घंटे से घटकर सिर्फ 36 मिनट

क्षमताः प्रति दिशा प्रति घंटे लगभग 1,800 यात्री

केबिन क्षमताः लगभग 35 सीटें, अत्याधुनिक आरामदायक डिजाइन

तकनीकः वैश्विक मानकों पर आधारित उन्नत रोपवे प्रणाली

पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा

यह रोपवे परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। केंद्र सरकार की इस पहल का उद्देश्य देश में रोपवे नेटवर्क का विस्तार, पर्वतीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाना, और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।

परियोजना से न केवल केदारनाथ धाम की यात्रा सुगम होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, और पर्यटन उद्योग को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

अदाणी समूह को मिला Letter of Award (LoA)

करीब एक महीने पहले अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को इस परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (NHLML) से लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) प्राप्त हुआ था। इसके बाद कंपनी ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है।

आस्था और पर्यावरण में संतुलन पर फोकस

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की संवेदनशील पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए, अदाणी समूह ने परियोजना में पर्यावरणीय संरक्षण और स्थायी विकास पर विशेष बल दिया है। कंपनी का कहना है कि परियोजना से आस्था, सुविधा और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखते हुए विरासत और श्रद्धा की भावना को और सशक्त किया जाएगा।

केदारनाथ रोपवे से क्या होगा लाभ?

■तीर्थयात्रियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा सुविधा

■बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए यात्रा होगी सहज

■पर्यटन में तेजी और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा

■निर्माण व संचालन में हजारों लोगों को रोजगार

■प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही है: मोदी

कुरनूल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को 21वीं सदी के लिए एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला और इस सफलता का श्रेय आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दिया।

श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं।

इस अवसर पर सुपर जीएसटी सुपर बचत नाम की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र होगा और 21वीं सदी भारत और उसके 140 करोड़ नागरिकों की है।

प्रधानमंत्री ने कहा, आज, दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही है और आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण इस सफलता का आधार है।÷ उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की सफलता में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना और सतत विकास को गति देना है। उन्होंने कहा, देश भर में मल्टी-मॉडल बुनियादी ढाँचा तेज़ी से विकसित हो रहा है और हम गाँवों से शहरों और शहरों से बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं।÷ नई रेल लाइनों के शुभारंभ और रेल फ्लाईओवर के निर्माण के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और क्षेत्र में उद्योगों को नई गति प्रदान करना है। भारत के तकनीकी भविष्य में राज्य की भूमिका को और रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने घोषणा की कि गूगल आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा। इस एआई हब में अत्याधुनिक एआई अवसंरचना, विस्तारित डेटा सेंटर क्षमताएँ, बड़े पैमाने पर ऊर्जा संसाधन और एक उन्नत फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क होगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि गूगल के साथ इस सहयोग में एक 'नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे' का निर्माण शामिल है, जिसमें कई सबसी केबल शामिल होंगे जो विशाखापत्तनम में भारत के पूर्वी तट को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ेंगे।' उन्होंने कहा कि इससे भारत की तकनीकी क्षमताएँ बढ़ेंगी (विशेष रूप से उन्नत नाइट विज़न उपकरण, मिसाइल सेंसर और ड्रोन रक्षा प्रणालियों के निर्माण में) जिससे देश के रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने दोहराया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों की सफलता देखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से ही जीएसटी में बड़ी कटौती लागू कर दी गई है। उन्होंने 'सुपर जीएसटी - सुपर बचत' अभियान के सफल शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की और जीएसटी बचत उत्सव के आयोजन में आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश को उनके नेतृत्व के लिए बधाई दी।

सहकारिता मंत्री ? डॉ.धन सिंह रावत ने 24 किसानों को दिया 24 लाख का ब्याजमुक्त ऋण

पथ प्रवाह, बागेश्वर/देहरादून

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत नुमाइशखेत, बागेश्वर में ÷सहकारिता से पर्वतीय कृषि÷ थीम पर आयोजित सहकारिता मेले के तीसरे दिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 24 काश्तकारों को 24 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण और ऐठाण, दोफाड, काण्डा व छालीखांखर की चार एमपैक्स समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए। इसके साथ ही लेखक केशवानंद जोशी की पुस्तक 'शकुन्तला नाटक' का भी विमोचन किया गया।

सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जनपदों में सहकारिता मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक के प्रमुख उत्पाद को पहचान दिलाकर उसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है।

उन्होंने बताया कि अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याजमुक्त ऋण किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 31 लाख किसान सहकारिता विभाग से जुड़े हैं, जिनमें बागेश्वर के 57 हजार किसान भी शामिल हैं। सरकार किसानों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान कर रही है, जिससे 16 लाख किसानों और 8.5 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिला है।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पहले वर्ष 21,000, दूसरे वर्ष 50,000 और तीसरे वर्ष 1 लाख का लोन मिलेगा। इसके साथ ही महिला समूहों को 10 लाख तक का ऋण बिना गारंटर प्रदान किया जाएगा। नगर निकायों के ठेली-फड़ विक्रेताओं को 9 नवंबर के बाद 5,000 से 10,000 तक का ऋण 3 से 5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मंडुवा का मूल्य 48 प्रति किलो निर्धारित किया गया है और राज्य में आर्गेनिक खेती को सहकारिता मॉडल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 400 नाली भूमि साझा करके सामूहिक खेती की जाएगी और उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया, ÷किसान उत्पादन करें, उसे बेचने की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग निभाएगा।÷

सहकारिता मंत्री ने काफलीगैर में डिग्री कॉलेज के निर्माण और कपकोट उप जिला चिकित्सालय के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए अगले 45 दिनों में बागेश्वर में 20 नए डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मेले में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में सरकार की योजनाओं की जानकारी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है। स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चाँद लगा दिए।

कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि सहकारिता मेलों के माध्यम से महिला समूहों और ग्रामीण उत्पादकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल, मुख्य विकास अधिकारी आर. सी. तिवारी, उप निबंधक कुमाऊँ मंडल हरिश्चंद्र खंडूड़ी, सहायक निबंधक बागेश्वर आशीष शर्मा, सचिव महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक बागेश्वर मनोहर सिंह भंडारी, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष ललित लटवाल, अन्य विभागीय कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

एक नजर

उत्तराखण्ड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 : 'हिल्स टू हाई-टेक' थीम के साथ देहरादून में भव्य आयोजन

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखण्ड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित नवाचार, सुशासन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "उत्तराखण्ड एआई इम्पैक्ट समिट 2025" का आयोजन शुक्रवार, 17 अक्टूबर को होटल रामाडा, देहरादून में किया जा रहा है। इस साल समिट की थीम "हिल्स टू हाई-टेक" रखी गई है।

मुख्य अतिथि के रूप में जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार समिट को संबोधित करेंगे। उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY), इंडिया एआई मिशन, एनआईसी मुख्यालय, आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, यूकॉस्ट, यू.पी.ई.एस. जैसी अग्रणी संस्थाओं और प्रदेश के प्रमुख स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

समारोह का शुभारंभ डॉ. दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यूकॉस्ट के स्वागत भाषण और डिजिटल कुंभ विषय पर संबोधन से होगा। इसके बाद श्री मोहम्मद वाई. सफ़ीरुल्ला, निदेशक, इंडिया एआई मिशन द्वारा इंडिया एआई मिशन की विजन पर वक्तव्य प्रस्तुत किया जाएगा। एआई इन गवर्नेंस÷ पर उत्तराखण्ड शासन के आईटी सचिव की प्रस्तुति और मुख्य उद्बोधन राज्य मंत्री द्वारा दिया जाएगा। समिट के तकनीकी सत्र में आईआईटी रुड़की (TIDES), आईआईएम काशीपुर (FIED) और ओम्निप्रेजेंट टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एआई आधारित नवाचार और उद्यमिता पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त, STP। एवं ।IM काशीपुर समर्थित स्टार्टअप्स अपने इनोवेशन प्रस्तुत करेंगे। एनआईसी की एआई सेवाओं पर विशेष सत्र श्रीमती शर्मिष्ठा दास, उपमहानिदेशक, एनआईसी मुख्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। समिट का प्रमुख आकर्षण होगा पैनल चर्चा जिसका विषय है ÷वैश्विक एआई प्रवृत्तियाँ एवं विकास- उत्तराखण्ड पर प्रभाव÷, और इसकी अध्यक्षता प्रो. राम शर्मा, कुलपति, यू.पी.ई.एस. करेंगे। कार्यक्रम का समापन राम एस. उनियाल, महाप्रबंधक (इमर्जिंग टेक्नोलॉजी), आईटीडीए के धन्यवाद ज्ञापन के साथ होगा।

छात्र छात्राओं के बीच पहुंची साइबर सेल टीम

पथ प्रवाह, हरिद्वार।साइबर क्राइम सेल हरिद्वार की टीम गुरूवार को राजकीय इंटर कॉलेज ब्राह्मरु पहुंची। यहां टीम ने स्कूल की लगभग 250 छात्राओं और वंदना कटारिया स्टेडियम हरिद्वार में करीब 400 खिलाड़ियों को वर्तमान समय में हो रहे साइबर अपराध एवं साइबर अपराध से बचाव के तरीकों से अवगत कराया। इस दौरान पंपलेट वितरित किये गए। सार्वजनिक स्थानों में सुलभ दृश्य बिन्दु पर साइबर अपराध जागरुकता संबंधित पोस्टर चिपकाए गये। साइबर टीम ने बताया कि यदि अंजाने में कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे। यह सूचना आनलाइन टोल फ्री नंबर भी दी जा सकती है।

चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ 50 बेडेड उप जिला चिकित्सालय, में उच्चीकृत

पथ प्रवाह, देहरादून

अल्मोड़ा जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत कर दिया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अस्पताल में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ डिजिटल एक्स-रे मशीन और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य महानिदेशक को इस हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आम जनता को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 30 शैय्यायुक्त ष्टाष्ट को 50 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय में अपग्रेड किया गया है।

डॉ. रावत ने बताया कि 50 शैय्यायुक्त उप जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। साथ ही अस्पताल में नई डिजिटल एक्स-रे मशीन सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। एसडीएच मानकों के अनुरूप अवसंरचनात्मक कार्यों और आवश्यक पदों के सृजन हेतु स्वास्थ्य महानिदेशक को यथाशीघ्र प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि चौखुटिया में अस्पताल के उच्चीकरण से स्थानीय स्तर पर आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसका लाभ विकासखंड द्वाराहाट, भिकियासैण और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के कई गांवों तक पहुंचेगा, जिससे ग्रामीणों को उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अनूठी पहल: 132 ग्राहकों को लौटाए गए 1.73 करोड़ रुपये

पथ प्रवाह, हरिद्वार

वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के निर्देश पर हरिद्वार में आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान के तहत अनक्लेम्ड एसेट्स के निपटान और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल गार्डन व्यू में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि बैंकों में पड़ी निष्क्रिय या अप्रयुक्त जमा राशि को सही तरीके से उपयोग में लाया जाए और जमाकर्ताओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस विषय पर भविष्य में और बैठकों में भी समीक्षा की जाएगी।

इस कार्यशाला में पीएनबी, एसबीआई सहित जिले के सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी, एसईबीआई, म्युचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एलडीएम हरिद्वार दिनेश गुप्ता ने बताया कि हरिद्वार उत्तराखंड का पहला जिला है जिसने इस तरह का शिविर आयोजित किया। जिले में लगभग 76.31 करोड़ अनक्लेम्ड राशि पड़ी है, जिसे ग्राहकों को लौटाने के लिए यह पहल की गई। आज के शिविर में विभिन्न बैंकों द्वारा 132 लोगों को कुल 1.73 करोड़ अनक्लेम्ड राशि वापस की गई।

ग्राहकों को आरबीआई के उदगम ष्ठन्नरू पोर्टल (udgam.rbi.org.in) के जरिए निष्क्रिय खातों की जानकारी और दावा प्रक्रिया समझाई गई।

कार्यक्रम में शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा, पीएनबी के आंचल प्रमुख महाप्रबंधक अनुपम, एसबीआई महाप्रबंधक दीपेश राज, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हरिहर पटनायक, आरबीआई, नाबार्ड , जीआईसी, एलआईसी, एसईबीआई, म्युचुअल फंड और अन्य सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी तथा लगभग 200 ग्राहक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में एलडीएम हरिद्वार दिनेश गुप्ता ने सभी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारियों और उपस्थित ग्राहकों का धन्यवाद किया।

सांसद त्रिवेंद्र रावत बोले दीपावली का पर्व: स्वदेशी उत्पादों से घर सजाकर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प

पथ प्रवाह, हरिद्वार

भारतीय जनता पार्टी विधानसभा हरिद्वार ने दीपावली मिलन कार्यक्रम ÷एक शाम प्रभु श्रीराम के नाम÷ भजन संध्या का आयोजन किया। प्रेमनगर आश्रम में आयोजित भव्य समारोह में भगवान श्री राम का स्मरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और नगर निगम हरिद्वार की महापौर किरण जैसल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

प्रदेश में हाल ही में आई दैवीय आपदाओं में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प भी लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि कि दीपावली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वदेशी का उत्सव है। हमें हर घर को स्वदेशी उत्पादों से सजाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी अपनाने की दिशा में आगे आना होगा।

विधायक मदन कौशिक ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दीपावली की परंपराओं – जैसे घर की सफाई, पारंपरिक व्यंजन और दीप जलाने – को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हुए कहा कि यह पर्व सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महापौर किरण जैसल ने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि कि हम सभी को पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। स्वच्छ वातावरण ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि इस दीपावली मिलन ने न केवल खुशियाँ साझा करने का अवसर दिया, बल्कि समाज में एकता और समरसता का संदेश भी दिया।

कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया, जहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएँ दीं और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प लिया। भजन संध्या का संचालन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री दीपांशु विद्यार्थी ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे– पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार अरोड़ा, भाजपा के प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी विकास तिवारी, जिला महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट, सुभाष चंद्र अन्नू कक्कड़, पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, जिला उपाध्यक्ष आशु चौधरी, संदीप अग्रवाल, जिला मंत्री रिशु चौहान, पारुल चौहान, भाजपा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक सचिन अग्रवाल, महेंद्र धीमान, सुशील त्यागी, तरुण नैयर, पूर्व राज्य मंत्री सुशील चौहान, मास्टर नागेंद्र, पवन तोमर, ललित नैयर, नीरज त्यागी, भाजपा मंडल अध्यक्ष किशन बजाज, प्रशांत शर्मा, राजेंद्र कटारिया, शशांक भट्ट, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजन चतुर्वेदी, प्रीति गुप्ता, पार्षद ललित रावत, दीपक शर्मा, सपना शर्मा, मोनिका सैनी सहित अनेक गणमान्य कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।

डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जगजीतपुर में जोनल खेलकूद प्रतियोगिता में खेल भावना और प्रतिभा का शानदार संगम

पथ प्रवाह हरिद्वार।

डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, जगजीतपुर, हरिद्वार में 15 अक्टूबर 2025 को डीएवी स्पोर्ट्स, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली के तत्वावधान में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर खेल भावना, जोश और उमंग से सराबोर रहा।

पद्मश्री डॉ. पूनम सूरी जी, प्रधान, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में यह आयोजन हुआ। उनका यह स्पष्ट मत है कि ÷मानसिक और आत्मिक विकास तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ और सशक्त हो।÷ डीएवी संस्थाओं का उद्देश्य सदैव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रहा है – जिसमें शिक्षा के साथ खेलकूद एवं शारीरिक विकास को भी समान महत्व दिया जाता है। डीएवी स्पोर्ट्स संयोजक एवं पब्लिक स्कूल निदेशक डॉ. वी. सिंह के निर्देशन में उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय डीएवी खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड जोन के सभी 8 डीएवी विद्यालयों के कुल 447 प्रतिभागी (276 छात्र एवं 171 छात्राएँ) विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल हुए।

प्रतियोगिता में क्लस्टर 'ए' के स्कूलों में डीएवी जगजीतपुर, बीएमडीएवी हरिद्वार, डीएवी देहरादून और डीएवी कोटद्वार शामिल रहे, जबकि क्लस्टर 'बी' में डीएवी काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी के स्कूलों ने भाग लिया। विद्यालय में तीरंदाज़ी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, राइफल शूटिंग, हैंडबॉल तथा क्रिकेट सहित कई खेलों का आयोजन किया गया।

ध्वजारोहण और शपथ समारोह से हुआ भव्य शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार कपिल एवं पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक तरुण आर्य द्वारा डीएवी ध्वजारोहण के साथ हुआ। डीएवी गान के पश्चात विद्यालय की स्पोर्ट्स कैप्टन भूमि पटेल ने सभी प्रतिभागियों को खेल भावना, अनुशासन और ईमानदारी की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य मनोज कुमार कपिल ने कहा – ÷खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग, समर्पण और संयम की भावना का प्रतीक हैं। हमें सामूहिक किंतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं खेल भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।÷ उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रेरक शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा– ÷गीता के अध्ययन की तुलना में खेलों के माध्यम से आप स्वर्ग के अधिक निकट होंगे।÷ यह उद्धरण इस तथ्य को पुष्ट करता है कि एक संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए शारीरिक शक्ति, मानसिक सहनशक्ति और नैतिक चरित्र समान रूप से आवश्यक हैं।

राज्यभर के डीएवी विद्यार्थियों ने दिखाई खेल प्रतिभा

प्रतियोगिता में बालक व बालिका वर्ग के विभिन्न आयु वर्गों – अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 में रोमांचक मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, राइफल शूटिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो जैसी प्रतियोगिताओं में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

खेलों के साथ मिली प्रेरणा और आत्मविश्वास की ऊर्जा

समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। निर्णायकों, कोच एवं शिक्षकों के सहयोग से यह आयोजन सफल, अनुशासित और यादगार बना। सभी विजेता प्रतिभागी और टीमें अब डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स, जो कि नवंबर माह में दिल्ली-एनसीआर में आयोजित की जाएगी, में प्रतिभाग करेंगी। प्रधानाचार्य मनोज कुमार कपिल ने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि – डीएवी के विद्यार्थी न केवल अकादमिक क्षेत्र में बल्कि खेलों में भी उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। खेल हमें हार-जीत से परे एकता, अनुशासन और जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं।

मुख्य परिणाम - क्रिकेट (बालक वर्ग): अंडर-14, 17 और 19 तीनों वर्गों में क्लस्टर 'ए' विजेता एवं क्लस्टर 'बी' उपविजेता रहे।

बास्केटबॉल (बालक वर्ग): अंडर-17 वर्ग में डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल (हरिद्वार) विजेता रहा, जबकि डीएवी काशीपुर उपविजेता घोषित हुआ।

एथलेटिक्स (ओवरऑल ट्रॉफी)÷ क्लस्टर 'ए' से डीएवी कोटद्वार ने ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया।

विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में डीएवी देहरादून, डीएवी कोटद्वार और डीएवी हल्द्वानी के छात्रों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

लॉन्ग जंप और हाई जंप÷ डीएवी हल्द्वानी, डीएवी देहरादून एवं डीएवी कोटद्वार के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किए। शॉट पुट और डिस्कस थ्रो÷ डीएवी कोटद्वार, डीएवी काशीपुर और बीएमडीएवी हरिद्वार के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया।

राइफल शूटिंग (बालक वर्ग)÷ हरिद्वार के निशानेबाजों ने अपना दबदबा कायम रखते हुए सभी पदक अपने नाम किए।

जैवलिन थ्रो÷ बालिका वर्ग में डीएवी देहरादून की छात्राओं ने तीनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की।

हरिद्वार के मास्टर प्लान में कॉरिडोर समेत 250 आपत्तियां, उपाध्यक्ष सोनिका बोली होगी गहन समीक्षा

जनता की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करेगा एचआरडीए- उपाध्यक्ष सोनिका

पथ प्रवाह हरिद्वार। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) की उपाध्यक्ष सोनिका (आईएएस) ने गुरुवार को भल्ला कॉलेज, हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की के मास्टर प्लान 2041 को लेकर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने जनता की आपत्तियों और सुझावों को सुना। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार, एचआरडीए सचिव मनीष सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि अब तक लगभग 250 आपत्तियां और सुझाव मास्टर प्लान 2041 के

संबंध में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आपत्ति और सुझाव का विस्तृत विश्लेषण कर, जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। जनसुनवाई में कॉरिडोर निर्माण से संबंधित कई आपत्तियां भी दर्ज की गईं, जिनमें स्थानीय निवासियों ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय संतुलन से जुड़े मुद्दे उठाए। उपाध्यक्ष सोनिका ने आश्वासन दिया कि कॉरिडोर परियोजना से जुड़ी सभी आपत्तियों की गहन समीक्षा की जाएगी और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष ने कहा कि विकास योजनाएं तभी सार्थक होती हैं जब उनमें जनता की भागीदारी और हितों का समुचित ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए सभी बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे और अपने-अपने सुझाव व आपत्तियां प्रस्तुत कीं।

संपादकीय

शुद्धता की ओर निर्णायक कदम

त्योहारों का मौसम खुशियों और मिठास का प्रतीक होता है। दीपावली के आगमन पर जब बाजारों में रौनक बढ़ती है, तब कुछ असामाजिक तत्व इस पवित्र उत्सव की भावना पर आघात करते हैं। दूध, मावा, घी और मिठाइयों में की जाने वाली मिलावट केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे समय में उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा ÷मिलावट पर जीरो टॉलरेंस÷ अभियान निश्चित रूप से सराहनीय और समयानुकूल कदम है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध छेड़ा गया यह अभियान प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दीपावली से पहले राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाना, हर जिले में विशेष निगरानी दल बनाना और सरप्राइज निरीक्षण करना यह साबित करता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और सचिव खाद्य सुरक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशों पर गठित टीमों ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो कार्रवाई की है, वह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस परिणाम देने वाली है।

देहरादून में मिठाई और दुग्ध उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जांच, नमूने संग्रह और प्रयोगशाला परीक्षण यह दर्शाते हैं कि प्रशासन अब किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतना चाहता।

अमानतगढ़ में संयुक्त टीम द्वारा 10 क्विंटल मावा की जब्ती और रुड़की में बिना तापमान नियंत्रण के मिलावटी मावा सप्लाई करने वाले वाहन की रोकथाम, इस अभियान की गंभीरता को रेखांकित करती है। इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट संदेश गया है कि त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों को अब किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी।

सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर सक्रिय हैं, लेकिन इस लड़ाई में जनता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब तक उपभोक्ता स्वयं जागरूक नहीं होगा, तब तक मिलावटखोरी पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती।

सस्ती मिठाइयों और खुले मावे के प्रति लालच से बचना, उत्पाद की ब्रांड, पैकिंग और एक्सपायरी डेट की जांच करना – यही कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही, संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को देना नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम (स्रस्द्ध ष्ह) के तहत दोषियों पर कठोर दंड का प्रावधान है, परंतु वास्तविक परिवर्तन तब संभव है जब व्यापारी समुदाय शुद्धता और नैतिकता को व्यापार का आधार बनाए।

यह केवल कानून का भय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रश्न है। त्योहार की भावना तभी सच्ची होगी जब मिठास कृत्रिम न होकर ईमानदार हो।

उत्तराखंड सरकार का ÷मिलावट पर जीरो टॉलरेंस÷ अभियान उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम है। दीपावली की सच्ची मिठास वही होगी, जो शुद्धता और विश्वास से भरी हो। इस अभियान की सफलता प्रशासनिक सख्ती और जनता की सजगता–दोनों पर निर्भर करती है। जब शासन का इरादा दृढ़ हो और समाज का सहयोग पूर्ण, तब मिलावटमुक्त उत्तराखंड का सपना भी जल्द साकार होगा।

गरीबी है मानवता के भाल पर बड़ा कलंक

ललित गर्ग

विश्व समुदाय हर वर्ष 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन केवल एक स्मरण नहीं, बल्कि मानवता के समक्ष खड़ी सबसे बड़ी चुनौती पर मंथन का अवसर है। सभ्यता के विकास, तकनीकी प्रगति, आर्थिक विस्तार और वैश्विक व्यापार के बावजूद आज भी करोड़ों लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। गरीबी एक आर्थिक स्थिति मात्र नहीं है, यह मनुष्य की गरिमा पर सबसे बड़ा आघात है-यह उसके सपनों, आत्मविश्वास और अस्तित्व को कुचलने वाला सामाजिक अभिशाप है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में गरीबी को खत्म करने के प्रयासों और संवाद को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य गरीबी में जी रहे लोगों के संघर्ष को स्वीकार करना और गरीबी के विभिन्न आयामों, जैसे कि आय की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच की कमी आदि को संबोधित करना है। 2025 की थीम 'परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना' है। इस दिवस का उद्देश्य गरीबी और इसके कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, तथा गरीबी से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को उजागर करना है।

आज दुनिया में लगभग सत्तर करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक अत्यंत गरीबी का अंत किया जाए, परंतु यह लक्ष्य अभी भी दूर प्रतीत होता है। युद्ध, जलवायु परिवर्तन, असमान आर्थिक नीतियाँ, जनसंख्या वृद्धि और बेरोज़गारी ने गरीबी को नया रूप दिया है। अब गरीबी केवल रोटी की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की असमानता और सामाजिक अन्याय का भी प्रतीक बन चुकी है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं-÷गरीबी केवल आय का प्रश्न नहीं है, यह स्वतंत्रता की कमी है।÷ अर्थात जब किसी व्यक्ति के पास अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के अवसर नहीं होते, तभी वास्तविक गरीबी जन्म लेती है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में गरीबी घटाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग के अनुसार, 2013-14 में जहाँ देश की 29 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, वहीं 2019-21 तक यह घटकर लगभग 11 प्रतिशत रह गई। परंतु यह सफलता पूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि गरीबी का असर ग्रामीण इलाकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अभी भी अधिक है। गरीबी का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है-जहाँ गरीब बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते हैं, वहीं परिवार बीमारी का खर्च नहीं उठा पाते। यह चक्र दर चक्र उन्हें फिर गरीबी में धकेल देता है।

आजादी के अमृत काल में सशक्त भारत एवं विकसित भारत को निर्मित करते हुए गरीबमुक्त भारत के संकल्प को भी आकार देना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार ने वर्ष 2047 के आजादी के शताब्दी समारोह के लिये जो योजनाएं एवं लक्ष्य तय किये हैं, उनमें गरीबी उन्मूलन के लिये भी व्यापक योजनाएं बनायी गयी है। विगत ग्यारह वर्ष एवं मोदी के तीसरे कार्यकाल में ऐसी गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे भारत के भाल पर लगे गरीबी के शर्म के कलंक को धोने के सार्थक प्रयत्न हुए है एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों को ऊपर उठाया गया है। वर्ष 2005 से 2020 तक देश में करीब 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं तब भी भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां गरीबी सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी उन्मूलन के लिये उल्लेखनीय एवं सफलतम उपक्रम किये हैं, उन्होंने गरीबी को राष्ट्र निर्माण की केंद्र बिंदु नीति के रूप में प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को केवल कल्याण योजनाओं तक सीमित न रखकर आत्मनिर्भरता के आंदोलन में बदल दिया। जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी ने गरीबों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों के सिर पर छत का सपना साकार किया और अब तक चार करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्त जीवन दिया और यह योजना केवल गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि समानता और सम्मान का प्रतीक बनी। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने महामारी के कठिन दौर में गरीबों को सुरक्षा कवच दिया, वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान ने गरीबी उन्मूलन का दीर्घकालिक रास्ता रोज़गार, कौशल और स्वाभिमान के माध्यम से खोला। प्रधानमंत्री का यह कथन इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है-÷गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार नहीं, समाज को भी संवेदनशील बनना होगा। जब हर गरीब का सपना हमारा सपना बनेगा, तभी समृद्ध भारत बनेगा।÷

गरीबी केवल सरकारी योजनाओं से नहीं मिटेगी; इसके लिए एक व्यापक मानव-केंद्रित सोच की आवश्यकता है। शिक्षा को अधिकार नहीं, अवसर बनाना होगा, हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिलना चाहिए। समान आर्थिक अवसरों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई घटे। पूंजी का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण भी होना चाहिए। साथ ही, महात्मा गांधी के शब्दों में, ÷गरीबी सबसे बड़ी हिंसा है''-यह भावना हमारे सामाजिक चरित्र में उतरनी चाहिए। जब तक समाज करुणा और साझेदारी की भावना नहीं अपनाएगा, तब तक गरीबी का अंत संभव नहीं। भारत आज गरीबी उन्मूलन का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत कर रहा है-जहाँ विकास का अर्थ केवल जीडीपी नहीं, बल्कि गरीब का उत्थान है। यह संदेश दुनिया के लिए भी प्रेरणा है कि यदि सबसे बड़ा लोकतंत्र करोड़ों लोगों को गरीबी से ऊपर उठा सकता है, गरीब मुक्त भारत के सपने को आकार दे सकता है तो वैश्विक समुदाय भी एकजुट होकर यह कर सकता है। गरीबी केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, यह मानवता की परीक्षा है। जब तक दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति भूखा सोएगा, तब तक सभ्यता का विकास अधूरा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि ÷सच्ची प्रगति वही है, जिसमें समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो।÷ आज आवश्यकता है एक वैश्विक संकल्प की-'गरीबी नहीं, समानता हमारा धर्म बने।' जब हर राष्ट्र, हर समाज और हर व्यक्ति इस दिशा में जिम्मेदारी निभाएगा, तभी वह दिन आएगा जब गरीबी इतिहास का विषय होगी, वर्तमान का नहीं। गरीबी व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में अक्षम बनाता है। गरीबी के कारण व्यक्ति को जीवन में शक्तिहीनता और आजादी की कमी महसूस होती है। गरीबी उस स्थिति की तरह है, जो व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने में अक्षम बनानी है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के काले बादल, वर्ष के अंत तक बड़ा झटका संभव

सनत जैन

विश्व अर्थव्यवस्था आज एक गंभीर संकट की तरफ बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति, बढ़ता हुआ कर्ज और राजनीतिक तनाव आर्थिक गतिविधियों पर भारी असर डाल रहे हैं। अमेरिका, जिसे 1944 के बाद से सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था माना जाता रहा, अब कर्ज के बोझ तले दब गया है। अमेरिका का कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से 124 प्रतिशत अधिक हो गया है और देश अपने खर्चों को चलाने के लिए पुराने बॉन्ड बेचने पर निर्भर हो गया है। वहीं, अमेरिका में लॉकडाउन और लाखों लोगों की बेरोज़गारी ने डॉलर की वैश्विक पकड़ को भी कमजोर कर दिया है। कुछ वर्षों पहले तक वैश्विक कारोबार का लगभग 75 प्रतिशत डॉलर में होता था, जो अब घटकर करीब 56 प्रतिशत रह गया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे है, यह आंकड़ा जल्द ही 50 प्रतिशत से नीचे जा सकता है, जिससे डॉलर मुद्रा को सबसे बड़ा संकट झेलना पड़ेगा।

वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच सोने और चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता दिखाई देती है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। 2008 की अमेरिकी मंदी के बाद से दुनिया के फेडरल बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा और अपने खजाने में रखा। उस समय अमेरिका के पास लगभग 20,000 टन सोना था, जो अब घटकर मात्र 8,200 टन रह गया है। वहीं, चीन और भारत जैसे देशों में सोने का भंडार पिछले 15 वर्षों में लगातार बढ़ा है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश के नए विकल्प बनते जा रहे हैं। बिटकॉइन की कीमत पिछले एक साल में लगभग दोगुनी होकर 52 लाख रुपए से 1.1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन क्रिप्टो अभी भी सबसे जोखिम भरी मुद्रा मानी जाती है। एथेरियम, सोलाना, डोजकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी भी बाजार में सक्रिय हैं और वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाने का कारक बन सकती हैं।

विश्वविख्यात लेखक और आर्थिक विशेषज्ञ रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने 'रिच डैड पुअर डैड' जैसी चर्चित किताबें लिखी हैं, का मानना है कि बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित विकल्प नहीं है। उनका कहना है कि 2026 के अंत तक कर्ज और मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट आना तय माना जा सकता है। ऐसे समय में निवेशकों को अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए। कियोसाकी के अनुसार, नगदी को छोड़कर निवेश सोने, चांदी, म्युचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे विकल्पों में किया जाना चाहिए, जहां अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो।

पिछले 30 वर्षों में वैश्विक कर्ज की गंगा लगातार तेजी के साथ बढ़ती रही है। विश्व के सभी देशों की सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय संस्थाएँ और यहां तक कि 80-90 फीसदी परिवार भी कर्ज में डूब चुके हैं। आमदनी के मुकाबले खर्च लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देशों का कर्ज बेहिसाब बढ़ रहा है। अमे?रिका ने ईराक से लेकर अभी तक सैकड़ों प्र?तिबंध लगाकर डालर से कारोबार रोकन और डालर जप्त करने का जो खेल खेला है, उससे डालर की ??विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त होने से डॉलर का प्रभुत्व लगातार घट रहा है। इसके कारण ब्रिक्स देशों की मुद्रा, यूरो, चीन का युआन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विकल्पों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। इस परिदृश्य में सोना और चांदी न केवल सुरक्षित निवेश बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वैश्विक कारोबार में स्वीकार्य विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हर दल को बग़ावत और भितरघात का भय

कांतिलाल मांडोत

बिहार विधानसभा में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटे दलों को विस्मृत नही किया जा सकता है। ये दल वोट काटने में अहम भूमिका में रहते है। एआईएमआईएम, आप व जनसुराज सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को शुरू होगी। अपने अपने हिसाब से सभी दल चुनाव प्रचार में लग गए है। मायावती में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एनडीए की घटक दलों के चिराग पासवान की पार्टी कई अलग रंग न दिखा दे। जैसे 2020 में दिखाया गया था। बिहार में भाजपा के पास जनमत है। इस बार जेडीयू 101सीटो पर चुना लड़ रही है। जबकि भाजपासौ सीटों पर चुनाव मैदान में है। प्रशांत किशोर सभी पार्टियों पर चुनाव लड़ने की बात करते है। उनके निशाने पर एनडीए और महागठबंधन है। उनका कहना है कि 15 साल लालू और 20 साल नितीश के शासनकाल में बिहार बेहाल है। इस बार प्रादेशिक पार्टिया गणित बिगाड़ भी सकती है तो नीतीश को फायदा पहुंचा भी सकती है। गोपालगंज में ओवैसी वोट काटने में सफल नही हुए तो यहां आरजेडी की सफलता निश्चित है। बिहार में भ्रष्टाचार के लिए लालू का नाम हर चुनाव में उछलता है। उधर,हर घर मे एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने की बात कहने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी पर सीधा निशाना साधा है कि अगर थोड़ी सी नैतिकता बाकी है तो नौकरी के बदले हड़पी गई जमीन लौटाने की घोषणा करे। उल्लेखनीय है कि रेलमंत्री के कार्यकाल में लालू ने लोगो को नौकरी के बदले जमीन हड़प ली थी। उनके हाव भाव मे बैचेनी, घबराहट और हताशा साफ झलकती है। कुशवाहा ने कहा कि जिस नेता के पास नीति और नियत न हो,वह आधारहीन बयानबाजी के सहारे अपना राजनीतिक चेहरा तो चमका सकता है,लेकिन बिहार की जागरूक जनता को बेवकूफ बनाने में कभी सफल नही होगा।

भाजपा अपने वैचारिक आंदोलन के उफान पर थी। उसके रथी लालकृष्ण आडवाणी की राम रथयात्रा बिहार में लोकतंत्र की भूमि कहे जाने वाले हाजीपुर पहुंचने वाली थी। जिसे रोकने के लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया था कि रथ को गांधी सेतु पार नही करने देंगे। उसी वक्त संघ की पृष्ठभूमि से बीजेपी का युवा चेहरा उभर रहा था। उसने लालू की सत्ता को चुनौती दी और ऐलान किया कि राम रथ यात्रा को हाजीपुर रोकने दिया जायगा। तब नित्यानंद राय ने महापंचायत बुलाकर ऐसा जनसमर्थन जुटाया कि लालकृष्ण आडवाणी का रथ हाजीपुर में रोकने का साहस नही जुटा पाई। राजनीति में नैतिक मूल्यों की तरजीह दी। उधर,वैशाली जिले में पप्पु यादव ने अचार संहिता का उल्लंघन किया। बाढ़ पीड़ितो को नकद राशि दी गई। बिहार की राजनीति में ओवैसी ने कदम ताल बढ़ाए है। उनकी महत्वकांक्षा है कि वे मुसलमानों के सबसे नेता बन जाए। अनेक राज्यो में उनकी पार्टी का विस्तार होने लगा है। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसीहा बनना है तो हिंदी बेल्ट के मुस्लिम प्रभाव वाले राज्यो में अपने पैर फैलाने है और वे कर रहे है। अरविंद केजरीवाल की महत्वकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की थी। लेकिन उनका नाम भ्रष्टाचार में उछलने और दिल्ली में करारी हार के बाद केजरीवाल की साख में भारी कमी आई है। अब देश मे लोग उनको याद नही करते है। हर चुनाव में राज्य जितने की बात करने वाले केजरीवाल की दशा और दिशा दोनो बदल चुकी है। राजनीति करने आने वाले नेताओं में नैतिकता,प्रमाणिकता होनी चाहिए। लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार में अपने दामन पर दाग लगा दिया। अब उनकी राजनीतिक विरासत में उनके पुत्र की राजनीतिक महत्वकांक्षा दबती दिखाई देती है। बिहार में जनमत सर्वेक्षण में एनडीए की सरकार की संभावना जताई जा रही है। जनसुराज पार्टी की 13.3 प्रतिशत लोगो के समर्थन में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में अनेक दल चुनाव मैदान में है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा है। लेकिन इनकी राह आसान नही है। सतारूढ़ एनडीए 20 साल में सत्ता में है। पार्टी के पास बहुमत है जबकि सरकार में नीतीश की भूमिका सराहनीय रही है। बिहार में करिश्माई नेता तो मोदी है और मोदी के नाम पर मतदाता जान चिटकने के लिए तैयार है। बिहार चुनाव में कथनी और करनी के हिसाब से भाजपा को तरजीह दी जाती है। बिहार में नीतीश कुमार बेदाग नेता है और मतदाताओ के लिए निष्पक्ष और न्यायनीति के लिए सुशासन बाबू लोगों की प्राथमिकता है। इन दलों से चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान खड़ा होगा। अनेक दल चुनाव में खड़े होने की वजह से वोटो की हिस्सेदारी में विभाजन होगा। इन सारे माहौल में कांग्रेस अपना आधार बनाने की फिराक में है। बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है। मौजूदा सियासी शून्य की स्थिति में राजनीतिक दल अपने लिए अच्छा मौका तलाश सकते है। लेकिन यह हकीकत उनके मंसूबो पर पानी फेर सकती है।

एक नजर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में की विधिवत पूजा-अर्चना

पथ प्रवाह, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खटीमा स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में मंदिर में घंटी भी चढ़ाई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के मंदिर पहुँचने पर श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंदिर परिसर में उपस्थित महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने फूल-मालाओं और जयकारों के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक धरोहर ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बताया कि हमारा राज्य देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ के हर मंदिर और धाम में लोक आस्था का अनमोल खजाना बसता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार पवित्र स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दायित्वधारी फरजाना बेगम, अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा-मेलाघाट सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का 20.89 करोड़ रुपये से शिलान्यास किया

राज्य मार्ग-107 का 11.50 किमी लंबा पुनर्निर्माण, सड़क सुरक्षा, ड्रेनेज और सीमावर्ती कनेक्टिविटी में सुधार से क्षेत्र का विकास होगा तेज

पथ प्रवाह, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा-मेलाघाट राज्य मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 107) के पुनर्निर्माण कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर शिलान्यास किया। यह परियोजना ?20.89 करोड़ की लागत से संचालित की जाएगी। कार्य के अंतर्गत 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण, केसी ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा उपाय, रोड साइनएज की स्थापना, तथा टीबीएम एवं बीसी तकनीक द्वारा सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह सड़क केवल खटीमा क्षेत्र के विकास की धुरी नहीं है, बल्कि भारत-नेपाल सीमावर्ती संपर्क का भी महत्वपूर्ण मार्ग है। सड़क के सुधारीकरण से न केवल खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात सुनिश्चित होगा, बल्कि सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन और शिक्षा के अवसरों को भी नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क निर्माण के साथ भू-कटाव रोकने और स्थानीय जल निकासी व्यवस्था के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा शिक्षा का हब बन चुका है, जहाँ न केवल प्रदेश बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के हर क्षेत्र को सुगम, सशक्त और समृद्ध बनाना है। विकास की हर परियोजना जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, और खटीमा-मेलाघाट सड़क परियोजना इस दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ÷कनेक्टिविटी ही विकास की रीढ़÷ के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई और अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उपस्थित जनसमूह को आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और कहा कि पर्वों के अवसर पर राज्य की सुरक्षा, सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दायित्वधारी फरजाना बेगम, अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर 09 मोबाइल मेडिकल यूनिट को किया रवाना

हंस फाउंडेशन, हिन्दुस्तान जिंक व ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों को मिलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की नई सौगात

पथ प्रवाह, खटीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अपने निजी आवास नगला तराई, खटीमा से 09 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम्बुलेंस) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 08 मोबाइल यूनिट हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से तथा 01 यूनिट हिन्दुस्तान जिंक और ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से प्रदत्त है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस अवसर पर कहा कि हंस फाउंडेशन, हिन्दुस्तान जिंक कंपनी एवं ममता संगठन के ये सराहनीय प्रयास राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल स्वास्थ्य सेवा यूनिट ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी, जिससे जनता को समय पर उपचार, जांच एवं परामर्श की सुविधा उनके निकट ही उपलब्ध होगी। हंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर युद्धवीर सिंह ने जानकारी दी कि फाउंडेशन द्वारा दी गई 08 मोबाइल यूनिट में से 04 यूनिट जनपद उधम सिंह नगर में एवं 04 यूनिट जनपद नैनीताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। वहीं हिन्दुस्तान जिंक कंपनी की निदेशक अनामिका झा ने बताया कि राजस्थान के चार जनपदों के साथ-साथ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर और किच्छा क्षेत्र के 25 ग्रामों में सचल चिकित्सा वाहन सेवाएं शुरू की गई हैं। इन वाहनों में डॉक्टर, स्टाफ नर्स एवं काउंसलर नियुक्त किए गए हैं, जो गांव-गांव जाकर परामर्श, जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा में 215 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज का किया लोकार्पण

खटीमा में राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना से बढ़ी देशभक्ति की भावना, पीएम-कुसुम योजना की जानकारी भी किसानों को दी गई

पथ प्रवाह, खटीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंजाबाग तिराहा, खटीमा में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई विभाग द्वारा 47.42 लाख रुपये की लागत से स्थापित 215 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूजा-अर्चना कर फीता काटा और ध्वजारोहण किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह ध्वज यहाँ खड़ा रहेगा और हर नागरिक को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करेगा।

इस अवसर पर लघु सिंचाई विभाग ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोलर प्रदर्शनी भी आयोजित की। प्रदर्शनी में किसानों और जनता को योजना की विस्तृत जानकारियां दी गई, ताकि उन्हें योजना के लाभ और कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी मिल सके। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जामंत्री श्रीमती फरजाना बेगम, अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, मोहनी पोखरिया, किशन सिंह (किन्ना), जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, मुख्य चिकित्साधिकारी के. के. अग्रवाल, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग सुशील कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही।

केंद्रीय टास्क फोर्स ने देहरादून में सराहा उत्तराखण्ड का बिजनेस सुधार मॉडल

पथ प्रवाह, देहरादून

भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय की उच्चस्तरीय टास्क फोर्स ने आज देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य में डीरिग्यूलेशन और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस पहल की प्रगति की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सुश्री मीता राजीवलोचन एवं मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने संयुक्त रूप से की।

बैठक में टास्क फोर्स ने डीरिग्यूलेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिक क्षेत्रों की विस्तृत समीक्षा की। इसमें विनियमों के सरलीकरण, अनुपालन बोझ में कमी, तथा निवेश-अनुकूल वातावरण सृजन के लिए आगे की रणनीतियों पर गंभीर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई यह डीरिग्यूलेशन पहल, जिसे भारत सरकार के कैबिनेट सचिव व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहे हैं, राज्यों को भूमि, भवन और निर्माण, श्रम, उपयोगिताएं एवं अनुमतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियमों के सरलीकरण और सुधार में मार्गदर्शन देती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक विश्वास-आधारित, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल शासन प्रणाली का निर्माण करना है। टास्क फोर्स ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सुधारों के क्षेत्र में किए गए सक्रिय प्रयासों की सराहना की और राज्य को अंतरविभागीय समन्वय एवं डिजिटल एकीकरण को और मजबूत करने हेतु प्रोत्साहित किया, ताकि सुधार की गति निरंतर बनी रहे।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव विनय शंकर पांडे, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग डॉ. सौरभ गहरवार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी से उठाई मांग-बस अड्डा चौक का नाम हो 'राज्य निर्माण आन्दोलनकारी चौक', बने स्मारक और मीटिंग हॉल

पथ प्रवाह,ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। राज्य निर्माण के संघर्ष में अग्रणी रहे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त समिति ने गुरुवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य को ज्ञापन सौंपकर राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। समिति के केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विजेन्द्र पोखरियाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और पहचान को सशक्त रूप देने का समय आ गया है।

समिति ने जिलाधिकारी का धराली आपदा के दौरान दिखाए गए मानवीय संवेदना और नेतृत्व क्षमता के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने पीड़ितों के बीच रहकर राहत कार्यों का संचालन किया, वह प्रशंसनीय और प्रेरणादायी है।

ज्ञापन में प्रमुख मांग की गई कि उत्तरकाशी बस अड्डा चौराहे का नाम 'राज्य निर्माण आन्दोलनकारी चौक' रखा जाए और वहां एक स्मारक या प्रतीक चिह्न स्थापित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी को राज्य आंदोलन की भावना से परिचित कराया जा सके।

समिति ने यह भी प्रस्ताव रखा कि जिला चिकित्सालय गेट के सामने गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित जर्जर शिक्षा विभाग भवन को राज्य आंदोलनकारियों के हवाले किया जाए, ताकि उसे 'राज्य आन्दोलनकारी भवन' के रूप में विकसित किया जा सके। इसे मीटिंग हॉल एवं निःशक्त आंदोलनकारियों के अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाए।

आन्दोलनकारियों ने कहा कि जनपद मुख्यालय में राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों का भव्य स्मारक बनाया जाना भी समय की आवश्यकता है, ताकि उत्तराखण्ड राज्य की नींव रखने वाले त्याग और बलिदान को उचित सम्मान मिल सके।

समिति ने यह भी नाराज़गी जताई कि पिछले वर्ष राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान आंदोलनकारियों की उपेक्षा की गई और राज्य विरोधियों को मंच पर सम्मानित किया गया, जिससे जनपद के आंदोलनकारी आहत हैं। समिति ने मांग की कि इस वर्ष 9 नवम्बर 2025 को राज्य स्थापना दिवस स्वतंत्रता दिवस की तर्ज पर जनपद की सभी तहसीलों में भव्य रूप से मनाया जाए तथा आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के साथ सम्मानित किया जाए।

जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन पर चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त समिति उत्तराखण्ड के केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विजेन्द्र पोखरियाल, जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, यमुना घाटी बड़कोट ब्लॉक अध्यक्ष बाल गोविन्द डोभाल, जिला संरक्षक चतर सिंह राणा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुशहाल सिंह बिष्ट, जगदीश प्रसाद भट्ट, उपाध्यक्ष जयेंद्र सिंह बिष्ट, जेठूलाल भारती, जिला महासचिव लाखीराम नौटियाल, मूलचन्द सिंह पंवार, मोहनानन्द बिजल्वाण, जिला सचिव धर्म सिंह मेहर, राजेन्द्र नौटियाल, रमेश सिंह राणा, शुरबीर सिंह राणा, खुशपाल परमार, वशिष्ठ उनियाल, बृजमोहन उनियाल, सुरेन्द्र सिंह चौहान, चन्द्र भूषण उनियाल, शम्भु प्रसाद नौटियाल, कृपाल सिंह मेहर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशीला असवाल, जिला उपाध्यक्ष चन्द्रकान्ता सेमवाल आदि शामिल रहे।

समिति ने कहा कि राज्य आंदोलन की आत्मा आज भी जनता के दिलों में जीवित है, बस शासन-प्रशासन को चाहिए कि वह संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर इन आंदोलनकारियों की गरिमा को पुनर्स्थापित करे।

केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विजेन्द्र पोखरियाल ने मुलाकात के बाद बताया कि जिलाधिकारी से बैठक बहुत सकारात्मक और सार्थक रही। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने ज्ञापन में उठाए गए हर मुद्दे पर सहमति और गंभीरता व्यक्त की है, जिससे राज्य आंदोलनकारियों में नई ऊर्जा और उम्मीद जगी है।

उत्तरकाशी जिले में बढ़ी मतदान व्यवस्था की मजबूती, 14 नए मतदेय स्थलों को मिली मंजूरी

भारत निर्वाचन आयोग ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में संशोधन एवं पुनर्निर्धारण प्रस्तावों को दी मंजूरी

अब तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 558 केंद्रों पर होगा मतदान

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 01-पुरोला (अ.जा.), 02-यमुनोत्री एवं 03-गंगोत्री में सम्मिलित कुल 544 मतदेय स्थलों के सापेक्ष संशोधन, परिवर्तन एवं पुनर्निर्धारण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर आयोग ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग को 01-पुरोला (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में 09 नये मतदेय स्थल तथा 02-यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 05 नये मतदेय स्थल सृजित किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत अब पुरोला (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में कुल 196 मतदेय स्थल, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 183 मतदेय स्थल तथा गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में 179 मतदेय स्थल हो गए हैं। इस प्रकार जनपद उत्तरकाशी में कुल 558 मतदेय स्थल स्थापित हो गए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि इसके अतिरिक्त जनपद में 23 भवनों के नाम संशोधन एवं 1 भवन परिवर्तन के प्रस्ताव भी निर्वाचन आयोग को भेजे गए थे, जिन पर भी आयोग की मंजूरी प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि जनपद के 14 नए मतदेय स्थल इस प्रकार हैं पुरोला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दणमाणा, कुफारा, मैराणा, बिणाई, कुमोला, किरोली, डाण्डागांव, जखोल (पश्चिमी भाग) एवं मुंगरा जबकि यमुनोत्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जुणगा, सर्प, कोटी (मणपा), राजगढी एवं नन्दगांव को नए मतदेय स्थलों के रूप में शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों का यह पुनर्निर्धारण निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं मतदाताओं के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग की अनुमति से अब सभी संबंधित क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक तैयारी एवं स्थलीय सत्यापन कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

धराली आपदा पर शासन की बड़ी समीक्षा बैठक मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने रखे प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास और आजीविका सुदृढ़ीकरण संबंधी सुझाव

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

धराली क्षेत्र में 5 अगस्त 2025 को आई विनाशकारी आपदा के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आजीविका सुदृढ़ीकरण की दिशा में शासन स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक का उद्देश्य धराली आपदा से संबंधित गठित समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श करना था। ज्ञात हो कि उत्तराखंड शासन द्वारा तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत धराली एवं आसपास के क्षेत्रों में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के कारण हुई जनहानि और संपत्ति क्षति की जांच एवं पुनर्वास कार्यों के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति में सचिव राजस्व डॉ. एस.एन. पांडेय (अध्यक्ष), मुख्य कार्याधिकारी यूकाडा डॉ. आशीष चौहान तथा अपर सचिव हिमांशु खुराना को शामिल किया गया था। समिति को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, आजीविका को स्थिर और सुदृढ़ बनाने, एवं दीर्घकालिक पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। इस दौरान समिति ने मृतक, लापता एवं घायल व्यक्तियों के परिवारजनों के लिए राहत वितरण, पशुधन व कृषि भूमि क्षति का मुआवजा, आजीविका सहायता, और दीर्घकालिक पुनर्वास योजना संबंधी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शासन को सौंपी हैं।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से समिति की रिपोर्ट पर बिंदुवार चर्चा की और पुनर्स्थापना एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए अन्य उपयोगी सुझाव मांगे। जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी पुनर्वास ढांचे के निर्माण, वैकल्पिक रोजगार सृजन, और आपदा न्यूनीकरण की दिशा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने जैसे सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डीएफओ डी.पी. बलूनी, अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी भटवाड़ी शालिनी नेगी, डीडीएमओ शार्दुल गुसाईं सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

धराली आपदा के बाद शासन की यह समीक्षा बैठक प्रभावित परिवारों के दीर्घकालिक पुनर्वास और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी में 'थूक जिहाद' का मामला, हिन्दू समाज में उबाल हिंदू सम्राट दर्शन भारती बोले देवभूमि की अस्मिता पर आघात बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर हो कठोर कार्रवाई

विश्व हिंदू बजरंग दल ने दी चेतावनी जायका रेस्टोरेंट का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त करने की मांग

पथ प्रवाह,उत्तरकाशी।

भगवान काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी उत्तरकाशी में बुधवार रात एक शर्मनाक और अमानवीय घटना के उजागर होने से पूरे जनपद में आक्रोश की लहर दौड़ गई। शहर के 'जायका रेस्टोरेंट' में कार्यरत एक कर्मचारी का बटर नान रोटी पर थूकते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय नागरिकों और हिन्दू संगठनों में भारी रोष फैल गया।

इस घटना को 'थूक जिहाद' बताते हुए हिंदू सम्राट दर्शन भारती, विश्व हिंदू बजरंग दल और अन्य धार्मिक संगठनों ने इसे देवभूमि की अस्मिता पर हमला बताया और दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

हिंदू सम्राट दर्शन भारती ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान धर्म, आस्था और पवित्रता से है। इस भूमि की गरिमा को कलंकित करने वाले तत्व जिहादी मानसिकता के पोषक हैं। प्रशासन यदि ऐसे कृत्यों पर कठोर कार्रवाई नहीं करता, तो हम सत्याग्रह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। दोषी पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो और जायका रेस्टोरेंट का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किया जाए। विश्व हिंदू बजरंग दल के जिला प्रभारी कीर्ति महर ने कहा कि यह देवभूमि की अस्मिता पर सीधा प्रहार है। यदि दोषी के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं जिला संयोजक सचेंद्र परमार ने कहा कि उत्तरकाशी जैसी पवित्र नगरी में इस तरह की घटनाएँ सांप्रदायिक सौहार्द को आघात पहुँचाती हैं। प्रशासन को इस रेस्टोरेंट को स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत न करे। प्रभारी निरीक्षक भावना कैंथोला ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद रेस्टोरेंट में कार्यरत कर्मचारी को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया था। पूछताछ के उपरांत उसे छोड़ दिया गया, किंतु उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ङ) एवं 274 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पवार ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना की जांच गंभीरता से की जा रही है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस ने रेस्टोरेंट से जुड़े तथ्यों की पुष्टि कर खाद्य सुरक्षा विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जायका रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और विभागीय जांच जारी है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय नागरिकों और धार्मिक संगठनों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मौखिक मांग की है कि इस जघन्य कृत्य को सामाजिक अपराध की श्रेणी में लाया जाए, दोषी को कठोर दंड दिया जाए और जायका रेस्टोरेंट का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'सशक्त बहना उत्सव' का किया शुभारंभ, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर का संदेश

पथ प्रवाह, टनकपुर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को छीनीगोठ, टनकपुर में आयोजित ÷मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव÷ में प्रतिभाग कर महिलाओं की उद्यमशीलता, पारंपरिक कौशल और आत्मविश्वास का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के मट्ठा निर्माण, ऐंपण कला, सोल्डरिंग, धान कूटने और लौह उत्पाद निर्माण में सक्रिय सहभागिता की।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं और बेटियों के उत्साह को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही 'विकसित उत्तराखण्ड' का सपना साकार होगा। राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं दे रही, बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्सव स्थल पर लगे विभिन्न लाइव स्टालों का अवलोकन किया और महिलाओं के श्रम व कौशल को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। उन्होंने स्वयं पारंपरिक मट्ठा बनाने, दीपावली की लाइटों की सोल्डरिंग, ओखल में धान कूटने और लौह उत्पाद निर्माण में भाग लेकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि? पारंपरिक खाद्य पदार्थ हमारी संस्कृति और स्वास्थ्य दोनों से जुड़े हैं। महिलाओं द्वारा उत्पादित ये वस्तुएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और ग्रामीण रोजगार से सीधे जुड़ी हैं। यही आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदने और उन्हें मार्केट से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिले में ऐसे उत्सव आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 'महालक्ष्मी किट' वितरण कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं को किट वितरण किया और बच्चों को स्वयं बाल भोग खिलाकर उनसे आत्मीय बातचीत की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे पोषण अभियान और प्रारंभिक शिक्षा को सफल बनाने की सबसे मजबूत कड़ी हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही राज्य सशक्त होगा। जब बहनें आत्मनिर्भर होंगी, तभी उत्तराखण्ड आत्मनिर्भर बनेगा। नारी तू शक्ति है, नारी तू सृष्टि की मुस्कान है; जब नारी सशक्त होगी, तभी उत्तराखण्ड समृद्ध होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नारी तू नारायणी' मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मातृशक्ति के कल्याण हेतु निरंतर कार्यरत हैं। उज्ज्वला, जन धन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 70 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 5 लाख से अधिक महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़ी हैं, जिनमें 1.65 लाख महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है और समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की है।

कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, प्रदेश महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, नगर पालिका अध्यक्ष चंपावत प्रेमा पांडे, टनकपुर नगर पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार, बनबसा नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी, जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी एस खाती सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और हजारों नागरिक उपस्थित थे।

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय प्रागंण में एबीवीपी की नई इकाई में दिखा देशभक्ति और उत्साह

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नई विश्वविद्यालय इकाई का गठन

पथ प्रवाह, हरिद्वार

बहादराबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की विश्वविद्यालय इकाई का औपचारिक रूप से गठन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एबीवीपी जिला संयोजक सौरभ शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने परिषद के उद्देश्य, संगठनात्मक स्वरूप और राष्ट्रनिर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला।

नवगठित पदाधिकारी और संगठन की कार्ययोजना

इस अवसर पर नगर मंत्री सूर्यांश ने नवीन इकाई की घोषणा करते हुए नवगठित पदाधिकारियों का परिचय कराया। उन्होंने संगठन की आगामी कार्ययोजना और लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह इकाई शिक्षा सुधार, छात्र हित और राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पीयूष मलिक ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद सदैव राष्ट्रहित, शिक्षा सुधार और छात्र हितों के लिए कार्यरत रही है। उन्होंने नवगठित टीम को संगठन की मर्यादाओं एवं दायित्वों के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया।

नवगठित इकाई के पदाधिकारी

नवगठित इकाई में प्रमुख पदाधिकारियों के रूप में निम्न सदस्य चुने गए-

अध्यक्ष- शुभम मिश्रा, उपाध्यक्ष- वंदना, मंत्री- दीपांशु पड़लिया, सह मंत्री- हेमंत, मीडिया मंत्री- विनोद बैंलवाल, सोशल मीडिया मंत्री- नवीन जगूड़ी, छात्रा प्रमुख- अंकिता धीमान, सह छात्रा प्रमुख- भूमिका चौहान / मानसी स्स्नष्ठ संयोजक- आशीष जोशी / शौर्य भट्ट, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक- आयुष नौटियाल, स्स्न्रस् संयोजक- प्रांत प्रशांत / सुमित ढोंडियाल, खेल एवं क्रीड़ा संयोजक- पीयूष मलिक, शोध प्रमुख- दीपांकर वर्मन

कार्यक्रम का संचालन छात्रसंघ सचिव आशीष ने किया। समारोह में छात्र शिवांगी, राणा सूर्य प्रताप, सुमित, आदित्य सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित थे।

देशभक्ति और उत्साह का माहौल

समारोह उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में सम्पन्न हुआ। नए पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कर संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि वे छात्र हित, शिक्षा और राष्ट्रहित में सक्रिय योगदान देंगे।

कनखल पुलिस ने व्यापार मंडल और एसपीओ के साथ की बैठक

पथ प्रवाह हरिद्वार। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कनखल पुलिस ने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों और एसपीओ व सीएजी सदस्यों के साथ बैठक की। व्यापार मण्डल सदस्यों के साथ सुरक्षा और व्यवस्था दोनों ही मुद्दों पर गंभीरता के साथ चर्चा की गई।

थाना कनखल पर आगामी त्यौहार दीपावली के दृष्टिगत थानाध्यक्ष कनखल द्वारा कनखल के व्यापार मंडल अध्यक्ष, पटाखा व्यापारियों एवं शहर के गणमान्य व्यापारियो के साथ बैठक की गई। निर्देश दिए की पटाखा एक अति ज्वलनशील पदार्थ की श्रेणी में आता है सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बताया कि निर्धारित स्थानों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। सभी लोगों से अतिक्रमण/यातायात पर विशेष वार्ता की गयी। सभी के सुझाव भी साझा किये गए।

अपील की गयी कि अतिशबाजी के समय आग लगने की घटनायें होती है तो फायर सर्विर्स की गाडियों के आने जाने के लिए पर्याप्त मार्ग दिया जाए। इसके लिए अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण को बाजारों से हटाकर रखें।

डीपीएस रानीपुर में बास्केटबॉल ब्याज ओपन टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने की होड़, खिलाड़ी दिखा रहे अपना दमखम

पथ प्रवाह हरिद्वार। दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर हरिद्वार में जोन-3 द डीपीएस बास्केटबॉल ब्याज ओपन टूर्नामेंट 2025 के दूसरे दिन भी खिलाड़ियों का जज्बा और जोश देखने लायक रहा। मैदान पर सभी टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करते दिखे। दर्शकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मैचों का आनंद लिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य डॉ. अनुपम जग्गा ने टूर्नामेंट के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि ÷खेल भावना और टीम स्पिरिट के साथ खेलना ही सच्ची जीत का प्रतीक है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन खेले गए मुकाबलों में रोमांच और प्रतिस्पर्धा दोनों का शानदार संगम देखने को मिला। पहले राउंड के रोमांचक मुकाबले में डीपीएस रानीपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डीपीएस झांसी को 45-10 के बड़े अंतर से पराजित किया। इसी क्रम में डीपीएस हल्दवानी ने सधे हुए खेल के दम पर डीपीएस बिजनौर को 30-7 से मात देकर अगले दौर में स्थान सुनिश्चित किया।

तीसरे मैच में डीपीएस वाराणसी और डीपीएस मेरठ के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें वाराणसी की टीम ने 30-26 के स्कोर से जीत दर्ज की। वहीं डीपीएस प्रयागराज और डीपीएस देहरादून के बीच खेले गए मैच में डीपीएस प्रयागराज टीम ने 27-12 से आसानी से विजय प्राप्त की। दिन के अंतिम मैच में डीपीएस आगरा और डीपीएस बरेली की टीमें आमने-सामने रहीं। दर्शकों की सांसें थमाने वाले इस मुकाबले में बरेली ने 36-34 के बेहद करीबी अंतर से जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। खबर लिखे जाने तक क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जारी थे। कल टूर्नामेंट के अंतिम दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनका दर्शकों और खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार है। कल टूर्नामेंट के समापन दिवस पर सेमीफाइनल और फाइनल मैचों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ टीमें आमने-सामने होंगी। विजेता टीम को न केवल ÷चैंपियन ट्रॉफी÷ से सम्मानित किया जाएगा, बल्कि खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी प्रदान किए जाएंगे। समापन समारोह में विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण, अभिभावकगण एवं खेलप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। टूर्नामेंट के इस गौरवशाली समापन के साथ डीपीएस रानीपुर खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम करेगा।

पिथौरागढ़ में सुशासन और विकास को नई दिशा देंगे जिलाधिकारी आशीष भटगांई

रोजगार, पर्यटन और कृषि पर रहेगा विशेष फोकस

पथ प्रवाह, संवाददाता जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़

पिथौरागढ़ जनपद के नव नियुक्त जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कार्यभार ग्रहण के बाद प्रशासनिक सक्रियता का आगाज़ करते हुए गुरुवार को जिला कार्यालय परिसर में स्थित सभी शाखाओं एवं कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, अभिलेख संधारण, स्वच्छता व्यवस्था तथा कर्मचारियों की उपस्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ÷कार्यालय जनता की सेवा का केंद्र है, अतः प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है कि वह ससमय उपस्थित होकर जनता से जुड़कर उनके कार्यों को प्राथमिकता

से संपादित करे।÷

प्रेस ब्रीफिंग में साझा की विकास दृष्टि

निरीक्षण उपरांत जिलाधिकारी भटगांई ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से संवाद किया और जनपद के समग्र विकास से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं साझा कीं।

उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ भौगोलिक, रणनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। अतः जनपद के चौमुखी विकास के लिए पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने के लिए सभी अधिकारियों को टीमवर्क और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। भटगांई ने कहा कि कार्यालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा और प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने कार्यों में पूर्ण जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का परिचय दें।

रोजगार, पर्यटन और कृषि को मिलेगा नया आयाम

जिलाधिकारी ने कहा कि पिथौरागढ़ जनपद में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि साहसिक पर्यटन (स्त्र1द्दठ्ठह्लह्वह्द्द ञ्श्वह्लद्धह्वह्यद्ग), जड़ी-बूटी उत्पादन, सिट्रस (नींबू वर्गीय) फलों की खेती और कृषि जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इन क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए समन्वित कार्ययोजना पर कार्य करेगा। स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

जनसुनवाई व्यवस्था और फील्ड विज़िट होंगी सशक्त

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी नियमित फील्ड विज़िट करेंगे, ताकि समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग प्रमुख से अपेक्षा की जाएगी कि वे जनता के बीच जाकर संवाद करें, उनकी समस्याएं सुनें और सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करें।

भटगांई ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि पिथौरागढ़ को प्रशासनिक कुशलता, पारदर्शिता और विकास की नई पहचान मिले। उन्होंने विश्वास जताया कि जनसहभागिता और टीमवर्क के माध्यम से जिले को मॉडल जनपद के रूप में विकसित किया जा सकता है।

एक नजर

दीपावली पर्व पर सुगम यातायात व्यवस्था के लिए जारी किया ट्रैफिक प्लान

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़। त्योहारी सीजन में धनतेरस, दीपावली, भैया दूज आदि त्यौहारों के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में बढ़ने वाली जन एवं वाहन भीड़ को नियंत्रित करने तथा आमजन की सुविधा के लिए जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। पर्वों के दौरान दिनांक 17 अक्टूबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 09ऱ00 बजे से सायं 07ऱ00 बजे तक सीमालगैर बाजार, नया बाजार, सिल्थाम गन शॉप से गांधी चौक तक किसी भी प्रकार के वाहनों (टू व्हीलर/फोर व्हीलर) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यत ऱ प्रतिबंधित अवधि में उक्त बाजार मार्ग पर किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होगा। सीमलगैर बाजार आने वाले वाहनों को नगर निगम के पास निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क किया जाएगा। मालवाहक वाहन केवल रात्रि 09ऱ00 बजे के बाद ही बाजार में प्रवेश कर माल अनलोड करेंगे। रेता, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री लाने वाले डंपर/टिप्पर /केवल सायं 07ऱ30 बजे के बाद ही शहर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन से अनुरोध है कि वे निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करें एवं पुलिस को सहयोग प्रदान करें ताकि पर्वों का उत्सव शान्ति, सुरक्षा एवं सुगमता के साथ सम्पन्न हो सके।

छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ व उत्तर बस्तर नक्सल-मुक्त घोषित

नयी दिल्ली/रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र अब पूरी तरह नक्सल आतंक से मुक्त हो चुके हैं। कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इन इलाकों को सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सख्त रणनीति के बाद आज 'नक्सलमुक्त क्षेत्र' घोषित किया गया है।

श्री शाह ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा,÷यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर, जो कभी आतंक के ठिकाने हुआ करते थे, आज नक्सल आतंक से मुक्त घोषित किये गये हैं।÷

उन्होंने बताया कि अब केवल दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद के कुछ अंश शेष हैं, जिन्हें जल्द ही सुरक्षा बल पूरी तरह समाप्त कर देंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और कल 27 ने अपने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में कल 61 नक्सली मुख्यधारा में लौटे थे। इस तरह दो दिन में 258 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। शाह ने कहा कि वह हिंसा का मार्ग छोड़ने और देश के संविधान में फिर से आस्था व्यक्त करने के उनके निर्णय की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे इस तथ्य का पता चलता है कि इस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के अथक प्रयासों से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। शाह ने कहा,÷हमारी नीति स्प्ष्ट है- जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है और जो बंदूक उठाए रखना चाहते हैं उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। जो अभी भी नक्सलवाद के रास्ते पर चल रहें हैं मैं उनसे फिर अपील करता हूं कि वे अपने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट आयें।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अगले वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 में भाजपा सरकार के गठन के बाद से अब तक 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है।

स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर शिकंता, हरिद्वार पुलिस ने पकड़ा 10 क्विंटल मिलावटी मावा

पथ प्रवाह हरिद्वार। त्योहारों से पहले जनपद हरिद्वार की बुग्गावाला पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आयी है। पुलिस ने नकली और मिलावटी मावा सप्लाई करने वाले गिरोह भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 10 क्विंटल नकली मावा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर बुग्गावाला पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।

हरिद्वार के पुलिस कप्तान द्वारा आगामी त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत आम जनता की नसों मे जहर घोलने वाले नकली खाद्य पदार्थ (नकली मावा, नकली पनीर आदि) बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने करने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश के अनुपालन में थाना बुग्गावाला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चौकी अमानतगढ़ में बैरियर लगाकर आने जाने वाले वाहनो की सघन चैकिंग की। चैकिंग के दौरान एक महिन्द्रा कार को चैक किया गया तो वाहन में लगभग 10 कुन्तल नकली मावा प्लास्टिक के कट्टों में भरा पाया

गया। जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये बताई जा रही है। वाहन चालक मौ. आरिफ से पूछताछ की गयी तो उसने पुलिस को बताया कि वह इस नकली मावे को मुजफ्फरनगर से देहरादून शहर में बिक्री के लिए लेकर जा रहा था। मौके पर खाद्य विभाग की टीम को बुलाया गया। माल की सैंपलिंग कर शेष माल को मौके पर नष्ट किया गया। वाहन को मौके पर सीज कर चालक को आवश्यक कार्यवाही हेतु खाद्य विभाग की टीम के सुपुर्द किया गया।

भारत के तेल आयात के संबंध में ट्रम्प के बयान से देश-विदेश में हलचल

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस ताजा टिप्पणी से देश विदेश में राजनीतिक व राजनयिक हलकों में एक बड़ी हलचल पैदा हो गयी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल की खरीद बंद करने का आश्वासन दिया है और यह काम जल्द हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के वाशिंगटन में पत्रकारों के साथ बातचीत में दिये गये बयान को कुछ हलकों में भारत की ईंधन सुरक्षा नीति को प्रभावित करने का श्रेय लेने की अमेरिकी प्रशासन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। श्री ट्रम्प ने कहा , मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भारत (रूस से) तेल खरीद रहा था।.. और उन्होंने (मोदी) आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ी रोक है।

श्री ट्रम्प के इस दावे पर तत्काल विभिन्न हलकों से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गयीं ।

नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपनी ऊर्जा नीति तय करने का संप्रभु अधिकार रखता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत तेल और गैस का एक बड़ा आयातक है और अति अस्थिर वैश्विक तेल बाजार में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना लगातार देश की प्राथमिकता रही है।

विदेश मंत्रालय ने ज़ोर दिया कि देश की तेल आयात नीति इन दोहरे लक्ष्यों से प्रेरित है कि तेल-गैस की कीमतों में स्थिरता रहे और आपूर्ति सुरक्षित रहे। आयात के स्रोतों का विविधीकरण और उनकी व्यापकता इस नीति के प्रमुख स्तम्भ हैं।

मंत्रालय का कहना है कि भारत का यही व्यावहारिक रुख है कि देश पिछले एक दशक से भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को संतुलित करते हुए, अमेरिका सहित कई साझेदारों से तेल खरीदने के विकल्पों का विस्तार करने का प्रयास करता रहा है । भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की अमेरिका की वर्तमान सरकार की इच्छा भविष्य में ऐसे सहयोग के लिए शुभ संकेत है। यह भारत की संप्रभुता के प्रति सम्मान दर्शाता है।

ट्रम्प के बयान पर रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने प्रतिक्रिया देते हुए रुस से तेल खरीदने में भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रूस सरकार अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। श्री अलीपोव ने कहा, भारत और अमेरिका अपने निर्णय करने को स्वतंत्र हैं।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालयः 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन-249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई- www.pathpravah.com